



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 249      राँची, गुरुवार,      14 वैशाख, 1938 (श०)  
4 मई, 2017 (ई०)

---

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

-----  
संकल्प  
20 अप्रैल, 2017

**विषय:-** राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पी०जी० पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प सं०-143(9) दिनांक 6 अप्रैल, 2017 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में ।

**संख्या-166(9)--** राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पी०जी० पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु मेधा सूची तैयार करने के लिए MCI PG Medical Education Regulation, 2000 (Amended upto 8<sup>th</sup> February, 2016) के संगत अवतरण इस प्रकार हैं- “The Clause 9 under the heading SELECTION OF POST GRADUATE STUDENTS, as amended vide notification No.-MCI.18 (1) 2010-Med/49070 dated 21<sup>st</sup> December, 2010, following shall be added after sub clause (IV) which is as under, in terms of notification dated 15<sup>th</sup> February, 2012”-

“Provided that in determining the merit of candidates who are in service of Government/public authority, weightage in the marks may be given by the Government/ Competent Authority as an incentive at the rate of 10% of the marks obtained for each year of service in remote and/or difficult areas upto the maximum of 30% of the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test, the remote and difficult areas shall be as defined by State Government/Competent authority from time to time.”

Clause 9, sub clause VII में निम्नांकित प्रावधान है-

VII. 50% of the seats in Post Graduate Diploma Courses shall be reserved for Medical Officers in the Government service, who have served for at least three years in remote and/or difficult areas. After acquiring the PG Diploma, the Medical Officers shall serve for two more years in remote and/or difficult areas as defined by State Government/ Competent authority from time to time.

2. वर्तमान में विभागीय संकल्प सं०-154 दिनांक 11 अप्रैल, 2016 एवं WP(C) No.- 85/2016 (रोहित केशव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक 15 मार्च, 2016 को झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य चिकित्सा सेवा में 3 वर्ष से अधिक से कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों को पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उक्त संकल्प के कंडिका 4 में एम०सी०आई० के द्वारा अंकित प्रावधान के आलोक में पी०जी० डिप्लोमा कोर्स में नामांकन के उद्देश्य से झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत को छोड़कर शेष क्षेत्र को सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्र (Remote and/difficult areas) घोषित किया गया है।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील 8047/2016 में दिनांक 16 अगस्त, 2016 को पारित आदेश जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है:- In so far as Writ Petition No. 372/2016 even that should fail as we have held Regulation 9 to be a complete Code and a provision for determining inter-se-merit of the candidates including by giving weightage of marks as incentive to eligible in-service candidates who have worked in notified remote or difficult areas in the State, which is just, reasonable and necessary in larger public interest.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के फलस्वरूप राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम में तीन वर्ष से अधिक से कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ सभी डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बनाई जा रही मेधा सूची में भी दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत एवं कुल अधिकतम 30 प्रतिशत की अधिमानता दे सके।

4. राज्य में चिकित्सकों की कमी और राज्य चिकित्सा सेवा को आर्कषक बनाने के लक्ष्य से डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मेधा सूची बनाने में राज्य चिकित्सा सेवा अन्तर्गत Remote & Difficult area (अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के बाहर) में कार्यरत चिकित्सकों को ऊपर वर्णित Clause 9 Sub Clause IV के अनुरूप अंकों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एवं अधिकतम 30 प्रतिशत की अधिमानता की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर संकल्प सं०-143(9) दिनांक 6 अप्रैल, 2017 निर्गत किया गया है ।

5. उक्त निर्गत संकल्प के पश्चात् भी कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें उठाये गये बिन्दुओं का संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है :-

(क) विभागीय संकल्प सं०-143(9) दिनांक 6 अप्रैल, 2017 के आधार पर अधिमानता मात्र उन्हीं चिकित्सा पदाधिकारियों को दिया जाना है कि वर्तमान में Remote & Difficult area में कार्यरत हैं अथवा उन्हें भी जो पूर्व में Remote & Difficult area क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं पर वर्तमान में शहरी क्षेत्र में हैं ।

(ख) NEET-PG-2017 में परीक्षाफल में Not Qualified In-service अभ्यर्थियों को प्राप्त प्रोत्साहन अंक देय होगा या नहीं ?

6. उपर्युक्त कंडिका 5 (क) पर MCI PG Medical Education Regulation, 2000 के Clause 9 Sub Clause IV के आधार पर यह दिशा निर्देश दिया गया है कि राज्य चिकित्सा सेवा के चिकित्सकों को अधिमानता उस परिस्थिति में भी प्राप्त होगी जबकि उनके द्वारा अधिमानता प्राप्त करने की अवधि का कार्य Remote and Difficult area में किया गया है, भले ही वे वर्तमान में शहरी क्षेत्र में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त हैं ।

7. उपर्युक्त क्रमांक-5 (ख) पर विभागीय स्तर से MCI PG Medical Education Regulation, 2000 के Clause 9 Sub Clause IV के आधार पर यह व्याख्या किया गया था कि NEET-PG-2017 परीक्षाफल में Not qualified घोषित In-service अभ्यर्थियों को भी प्रोत्साहन अंक देय होगा, परन्तु इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्वद का अभिमत है कि MCI PG Medical Education Regulation, 2000 के Clause 9 Sub Clause III & Sub Clause V को दृष्टि में लेने पर NEET-PG-2017 के परीक्षाफल में Not Qualified घोषित In-service अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन अंक देय नहीं होगा ।

उपर वर्णित Clause 9 Sub Clause (III) & Sub Clause (V) इस प्रकार है:-

Sub Clause (III) - In order to be eligible for admission to any postgraduate course in a particular academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of 50% (Fifty percent) marks in

“National Eligibility-cum-Entrance Test for Postgraduate courses” held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the minimum percentage marks shall be 40% (Forty Percent) and in respect of candidates as provided in clause 9 (II) above with locomotory disability of lower limbs, the minimum percentage marks shall be 45% (Forty Five Percent) in the National Eligibility-cum-Entrance Test:

Provided when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in National Eligibility-cum-Entrance Test held for any academic year for admission to Post Graduate Courses, the Central Government in consultation with Medical Council of India may at its discretion lower the minimum marks required for admission to Post Graduate Course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the said academic year only.

Sub Clause (V) - No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as prescribed in sub Clause (II) above shall be admitted to any Postgraduate courses in the said academic year.

उपर अंकित MCI के संगत Regulation के Clause 9, Sub Clause III, IV एवं V को समेकित रूप से पढ़ते हुए परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची के अभिमत से सहमत हुआ जाता है कि NEET-PG-2017 के परीक्षाफल में Not Qualified घोषित In-service अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन अंक देय नहीं होगा ।

8. विभागीय संकल्प संख्या 143(9) दिनांक 6 अप्रैल, 2017 की घटनोत्तर स्वीकृति एवं कंडिका 6 एवं 7 में स्पष्टिकरण पर विभागीय संलेख संख्या- 162(9) दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के माध्यम से मंत्रिपरिषद् की दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के बैठक में मद संख्या 13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सुधीर त्रिपाठी,**  
अपर मुख्य सचिव ।

-----